उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

आदेश के विरुद्ध अपील संख्या **127** सन 2021

उत्तराखंड राज्य और अन्य. .....अपीलार्थी

बनाम

मेसर्स हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

श्री पी. सी. बिष्ट, राज्य/अपीलार्थियों के लिए अतिरिक्त सी. एस. सी.।

श्री सिद्धार्थ सिंह, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.
माननीय विवेक भारती शर्मा, जे.

(प्रतिःमाननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.)

यह अपील विविध मामले संख्या 42 सन 2020 में वाणिज्यिक न्यायालय , देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश 10.2.2021 दिनांकित के विरुद्ध प्रस्तुत है। उक्त निर्णय द्वारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 34 के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को विलम्ब के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने पहले अधिनियम की धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश, नई टिहरी के समक्ष आवेदन दायर किया था, जिसमें दिनांक 28/30.5.2018 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसे 3.7.2019 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु इच्छुक नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन की बहाली की मांग करते हुए जिला न्यायाधीश, नई टिहरी के समक्ष आवेदन दायर किया; इस बीच, देहरादून में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई और अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही की बहाली की मांग करने वाले आवेदन को वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया; वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून ने दिनांक 12.12.2019 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और उक्त आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा 2020 के आदेश से अपील संख्या 42 में चुनौती दी गई थी, जिसे इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आदेश दिनांक 18.2.2020 के माध्यम से निपटाया था। उक्त आदेश के पैरा 7 और 8 नीचे दिए गए है:

> ***"7.** हालाँकि, इस स्तर पर, प्रतिवादी निर्माण कंपनी के विद्वान अधिवक्ता, बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि यदि राज्य सरकार देहरादून में वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष विलम्ब माफी आवेदन के साथ पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक नया आवेदन दायर करते है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।*

8. *इसे ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्माण कंपनी द्वारा दायर किए गए निर्णय को रद्द करने का आवेदन पहले से ही निचली न्यायालय के समक्ष लंबित है, हम राज्य सरकार/अपीलार्थी को देहरादून में वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने के निर्देश के साथ वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं, जिस पर न्यायालय द्वारा हमारे उपरोक्त अवलोकन के आलोक में विचार किया जाएगा।"*

3. ए. ओ. संख्या 42 सन 2020 में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक न्यायालय , देहरादून के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत नया आवेदन दायर किया, जिसे विविध मामला संख्या 42 सन 2020 के रूप में दर्ज किया गया था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने दिनांकित 10.2.2021 के आदेश से विलम्ब के आधार पर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे इस अपील से चुनौती दी गई है।

4. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने इस मामले पर बहुत विस्तार से विचार किया और चर्चा की।आक्षेपित आदेश के पैरा 12 के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के समक्ष उपचार का अनुसरण करते समय अपीलकर्ता द्वारा बिताए समय को ध्यान में रखा है और माना है कि भले ही जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के समक्ष बिताया गया समय शामिल नहीं है, फिर भी अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन समय के बाद है।

5. हमारी सुविचारित मत में, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा लिए दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एक स्व-निहित संहिता है। अधिनियम की खंड 34 (3), जो अधिनियम की खंड 34 के तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करती है, निम्नानुसार हैः

"34. *मध्यस्थ फैसले को अलग रखने के लिए आवेदन /-* ***(1) .....***

(2) .....

(3) *रद्द करने के लिए कोई आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ फैसला प्राप्त हुआ था, या यदि धारा* ***33*** *के तहत अनुरोध किया गया था, तो उस तारीख से जिस दिन वह अनुरोध किया गया था मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया गया*

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था तो वह तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।"

6. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निहित प्रावधान के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि तीन महीने है, जिसे उचित मामलों में 30 दिनों की

अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 34 (3) के नियम में अभिव्यक्ति "लेकिन उसके बाद नहीं" यह स्पष्ट करती है कि न्यायालय, जिसके समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत एक मध्यस्थ फैसले को चुनौती दी गई है, परिसीमा की अवधि को 30 दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।इस पहलू को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *पी. राधा बाई बनाम पी. अशोक कुमार* के मामले में निपटाया है, जिसे (2019) 13 SCC445 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इस निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए है:

> ***"19.** यह विश्लेषण आवश्यक रूप से परिसीमा अधिनियम की धारा **29 (2)** से शुरू होना चाहिए, जिसमें कहा गया है:*
>
> ***29. (2)** जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग अवधि सीमा निर्धारित करता है, धारा **3** के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और के प्रयोजन के लिए किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी भी सीमा अवधि का निर्धारण करते हुए, धारा **4** से **24** (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे , और जिस सीमा तक वे ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।*
>
> *(बल दिया गया)*
>
> ***20.** धारा **29 (2)** को दो अंगों में विभाजित किया गया है।यह उक्त प्रावधान में "और" संयोजक से स्पष्ट है इन दोनों अंगों के बीच अंतर्संबंध पर इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने विद्याचरण शुक्ल बनाम खूबचंद बघेल मामले में विचार किया था।*
>
> ***32 .** धारा **34 (3)** की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए:*
>
> ***32.1.** मध्यस्थता अधिनियम के भाग **I** के तहत पारित पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा **34** ही एकमात्र उपाय है। धारा **34 (3)** एक सीमा प्रावधान है, जो उपचार प्रावधान में अंतर्निहित है। मध्यस्थता अधिनियम के भाग **I** के तहत पारित पुरस्कार को चुनौती देने के लिए सीमा अवधि की पहचान करने के लिए किसी को सीमा अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान को देखने की आवश्यकता नहीं है।*
>
> ***32.2.** सीमा अवधि की शुरुआत के लिए समय-सीमा धारा **34 (3)** में भी प्रदान की गई है, यानी वह समय जब आवेदन करने वाली पार्टी को "मध्यस्थता फैसला प्राप्त हुआ था" या धारा **33** के तहत सुधार और व्याख्या के लिए अनुरोध का निपटान किया गया था।*
>
> ***32.3.** धारा **34 (3)** धारा **33** के तहत फैसले की प्राप्ति या अनुरोध के निपटान की तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाती है। धारा **34 (3)** में इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है "तीन महीने बीत जाने के बाद रद्द करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है ।"वाक्यांश" बनाया नहीं जा सकता" **UNCITRAL** मॉडल कानून से है और इसका अर्थ "बनाया नहीं जा सकता" समझा गया है।ए.*

*बी. सी. कंपनी लिमिटेड बनाम **XYZ** कं. लिमिटेड मामले में सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः*

> *" इस चर्चा का प्रारंभिक बिंदु स्वयं आदर्श कानून होना चाहिए।समय के पहलू पर, अनुच्छेद **34 (3)** संक्षिप्त है। इसमें बस इतना ही कहा गया है कि निर्धारित तिथि से तीन माह बीत जाने के बाद आवेदन नहीं किया जा सकेगा । हालाँकि इस्तेमाल किए गए शब्द 'नहीं हो सकते' हैं, इनकी व्याख्या 'नहीं कर सकते' के रूप में की जानी चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि इरादा उस समय को सीमित करना है जिसके दौरान किसी फैसले को चुनौती दी जा सकती है इस व्याख्या का समर्थन मॉडल कानून के मसौदा तैयार करने वालों के बीच चर्चा से संबंधित सामग्री द्वारा किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय तीन महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात दायर किसी भी आवेदन पर विचार नहीं कर पाएगी क्योंकि अनुच्छेद **34** का मसौदा न्यायालय में किसी फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वव्यापी और एकमात्र आधार के रूप में तैयार किया गया है।. यह समय अवधि के किसी भी विस्तार का प्रावधान नहीं करता है और चूंकि न्यायालय केवल अनुच्छेद से आवेदन की सुनवाई करने के लिए अपना क्षेत्राधिकार प्राप्त करती है, इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति का मतलब है कि न्यायालय को समय बढ़ाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।"*
>
> *(जोर दिया गया)*

***32.4.** धारा **34 (3)** में सीमा प्रावधान में विलम्ब को माफ करने का भी प्रावधान है।सीमा अधिनियम की धारा **5** के विपरीत, पर्याप्त कारण दिखाने पर विलम्ब को मात्र **30** दिनों के लिए माफ किया जा सकता है। महत्वपूर्ण वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" एक फैसले को चुनौती देने के लिए एक बाहरी सीमा अवधि तय करने के विधायी इरादे को प्रकट करता है।*

***32.5.** एक बार जब मध्यस्थता फैसले को चुनौती देने की समय-सीमा या विस्तारित समय-सीमा समाप्त हो जाती है, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा **36** के तहत फैसले को लागू करने की अवधि शुरू हो जाती है। यह वाक्यांश से स्पष्ट है " जहां धारा **34** के तहत मध्यस्थ फैसले को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है"। पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा **34 (3)** के तहत निर्धारित अवधि और फैसले को निष्पादित करने के लिए धारा **36** के तहत प्रवर्तन अवधि की शुरुआत के बीच एक अभिन्न संबंध है।*

***33.** यदि सीमा अधिनियम की धारा **17** को धारा **34 (3)** के तहत सीमा अवधि निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता, तो इसके निम्नलिखित परिणाम होते :*

> ***33.1.** धारा **34 (3)** में, सीमा की गणना के लिए प्रारंभ अवधि फैसले की प्राप्ति की तारीख या धारा **33** के तहत अनुरोध के निपटान की तारीख है (यानी सुधार/अतिरिक्त पुरस्कार) । यदि धारा **34 (3)** के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए धारा **17** को*

*लागू किया जाना था, तो सीमा की प्रारंभिक अवधि कथित धोखाधड़ी या गलती की खोज की तारीख होगी धारा **34 (3)** के तहत परिसीमन का प्रारंभिक बिंदु परिसीमन अधिनियम से भिन्न होगा।*

***33. 2 .** धारा **34 (3)** का प्रावधान न्यायालय को तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किसी फैसले को चुनौती देने के लिए एक आवेदन पर विचार करने में सक्षम बनाता है, लेकिन केवल तीस तारीखों की अतिरिक्त अवधि के भीतर, लेकिन उसके बाद नहीं" ।"लेकिन उसके बाद नहीं" वाक्यांश के उपयोग से पता चलता है कि **120** दिनों की अवधि एक फैसले को चुनौती देने के लिए बाहरी सीमा है।यदि धारा **17** लागू होती, तो किसी फैसले को चुनौती देने की बाहरी सीमा **120** दिनों से अधिक हो सकती थी। वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" को अनावश्यक और निरर्थक बना दिया जाएगा।इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि मध्यस्थता अधिनियम की खंड **34 (3)** के प्रावधान में "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्द अनिवार्य प्रकृति के हैं, और नकारात्मक शब्दों में जोड़े गए हैं, जो संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। **(** एच. पी. राज्य बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स, असम अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड और अनिलकुमार जिनाभाई पटेल बनाम प्रवीणचंद्र जिनाभाई पटेल **)**।*

***34.** हमारे विचार में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34 (3)** की भाषा के साथ उपरोक्त विसंगतियां सीमा अधिनियम की धारा **17** के "स्पष्ट बहिष्कार" के समान हैं।*

7. इसी तरह का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *बीबीएम एंटरप्राइजेज बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* मामले में लिया गया था, जिसे (2020) 9 एससीसी 448 के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इस निर्णय के पैरा 3 और 8 नीचे दिए गए है :

***"5.** मुकदमेबाजी के पहले दौर में, धारा **34** की याचिका को विद्वान जिला न्यायाधीश ने **22-3, 2012** को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि **120** दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी, और इसलिए इस स्तर पर गुण-दोष में कोई हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।हालाँकि, **11-1-2013** के एक आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने इस फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया।*

***8.** सुनवाई के दौरान जो रोक दी गई है , वह जारी रहेगी। इन तथ्यों के सारांश से पता चलता है कि मामला पहले ही दो बार ऊपर-नीचे जा चुका है। हम केवल यह कह सकते हैं कि भले ही ऐसा नहीं लगता है कि , दूसरे दौर में, सीमा के बिंदु पर बहस की गई थी, क्योंकि डिवीजन बेंच द्वारा **11-1 2013** को नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया गया था, यह बिंदु भी न्यायालय के सामने एक दुखते अंगूठे की तरह था। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि सीमा बिंदु का कोई जवाब है। अन्यथा भी, विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेश का अवलोकन करने*

*पर, हमारा विचार है कि प्रतिवादी द्वारा दायर धारा **34** याचिका के निपटान के लिए पर्याप्त कारण दिए गए थे। हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि कोई कारण नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप रिमांड का आदेश दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाता है और विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक**22 12-2016** की पुष्टि की जाती है।"*

8. उपरोक्त कानूनी स्थिति होने के कारण, ए. ओ. संख्या 42 सन 2020 में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा की गई टिप्पणी पर अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया भरोसा अनुचित है।चूंकि क़ानून अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन के मनोरंजन पर रोक लगाता है, इसलिए, देरी को केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ताओं को विलंब माफ़ी आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

9. ऊपर दर्ज कारणों से, हम वाणिज्यिक न्यायालय , देहरादून द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई खामी नहीं पाते हैं। तदनुसार, हम इस आदेश से अपील को खारिज करते हैं।

(विवेक भारती शर्मा, जे.) **(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे)**

12 दिसंबर, 2023
पीआर